



नीति आयोग

# डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रोत्साहन योजना में दिखा जबरदस्त उत्साह डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए 45 दिनों में 7.6 लाख नागरिकों को मिले 117 करोड़ रुपये मूल्य के पुरस्कार

Posted On: 08 FEB 2017 6:28PM by PIB Delhi

नीति आयोग की दो प्रोत्साहन योजनाओं- लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना- के जरिये भारत में डिजिटल भुगतान को एक जन आंदोलन बनाने की पहल ने अपनी शुरुआत के बाद महज 45 दिनों में जबरदस्त परिणाम दिए हैं।

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 7 फरवरी 2017 तक 7.6 लाख ग्राहकों और व्यापारियों के बीच 117.4 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए रोजाना 15,000 ग्राहकों ने नकद वापसी प्राप्त की। साथ ही 90 अतिरिक्त ग्राहकों और 3,000 व्यापारियों ने साप्ताहिक पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये (प्रत्येक) जीते।

इन योजनाओं में पुरुषों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिखी। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सर्वाधिक विजेताओं के साथ शीर्ष पांच राज्यों के रूप में उभरे। हालांकि बहुसंख्य विजेता 21 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं लेकिन उनके आयु वर्ग में 15 से 66 वर्षों की विविधता दिखी। जन आंदोलन में बुजुर्गों की भागीदारी उस धारणा को चुनौती देती है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने में प्रौद्योगिकी उन्हें सबसे बड़ी समस्या दिखती है।

इन दोनों योजनाओं के विजेताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में भी विविधता दिखी और उसमें किसानों, व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, पेशेवरों, गृहणियों से लेकर सेवानिवृत्त व्यक्तियों तक शामिल हैं। पुरस्कार आंकड़ों के एक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ विजेताओं का भौगोलिक दायरा भी काफी विस्तृत रहा। दिलचस्प है कि डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल का लाभ भारत के हर कोने तक पहुंच गया और विजेताओं में लगभग हर राज्य के लोग दिखे।

उदाहरण के लिए, करनाल के असंध की नगर समिति के एक 66 वर्षीय किसान ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना के विजेता हैं। लकी ड्रॉ जीतने से महज एक महीना पहले ही उन्होंने डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की थी। अहमदाबाद के 23 वर्षीय टेक्नीशियन अंशुल गंगवार ने भी इस योजना के तहत 1,00,000 रुपये का पुरस्कार जीता है। नासिक के 27 वर्षीय पुलिस अधिकारी और डिजिटल भुगतान के जबरदस्त समर्थक मंगेश अनंतराव जाटव एक अन्य ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने उपयोगकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल भुगतान प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए यह पुरस्कार जीता।

व्यापारियों के बीच तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के दुकानदार आर दुरैराज ने व्यापारियों के लिए डिजि-धन व्यापार योजना के तहत 50,000 रुपये का साप्ताहिक पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक छोटे से कपड़े की दुकान के मालिक 37 वर्षीय यशपाल दर्बी भी हमारी डिजि-धन व्यापार योजना के तहत 50,000 रुपये के गौरवशाली विजेता हैं।

## योजना के बारे में:

नीति आयोग की दो योजनाएं हैं- लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) और डिजि-धन व्यापार योजना (डीवीवाई)। इन योजनाओं को 25 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया था और ये 14 अप्रैल 2017 तक खुली रहेंगी। इन योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को प्रोत्साहित करना है। इनके तहत कुल 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के लिए रोजाना 15,000 विजेताओं की घोषणा की जाती है। इसके अलावा हर सप्ताह कुल करीब 8.3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के लिए 14,000 से अधिक साप्ताहिक विजेता घोषित किए जाते हैं।

रूपे कार्ड, भीम / यूपीआई (भारत इंटरफेस फॉर मनी/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), यूएसएसडी आधारित \*99# सेवा और आधार सक्षम भुगतान सेवा (आईपीएस) का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता और व्यापारी दैनिक एवं साप्ताहिक लकी ड्रॉ पुरस्कार जीतने लेने के लिए पात्र हैं।

एनपीसीआई 14 अप्रैल 2017 तक 110 जगहों पर डिजि-धन मेला आयोजित करने के लिए भी सरकार के साथ काम कर रहा है ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उपरोक्त माध्यमों को प्रदर्शित किया जा सके। 7 फरवरी 2017 तक 45 डिजि-धन मेला आयोजित किए जा चुके हैं। इससे आम लोगों को डिजिटल भुगतान की आदत डालने में मदद मिलेगी।

## मुख्य बिंदु:

\* 9 नवंबर 2016 से 14 अप्रैल 2017 तक ग्राहकों और व्यापारियों द्वारा किए गए सभी लेनदेन इस योजना के तहत पुरस्कार जीतने के लिए पात्र होंगे।

\* ऐसे सभी लेनदेन 14 अप्रैल 2017 को आयोजित होने वाले मेगा ड्रॉ के लिए पात्र होंगे चाहे उसने दैनिक/साप्ताहिक पुरस्कार क्यों न जीता हो।

\* ग्राहकों के लिए 1 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के तीन मेगा पुरस्कार होंगे। व्यापारियों के लिए भी 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के तीन मेगा पुरस्कार होंगे।

\* हरेक दिन ड्रॉ के विजेताओं को विभिन्न केंद्रों पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति आयोग के प्रतिनिधियों और आम जनता की उपस्थिति में एनपीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

\* इन योजनाओं पर कुल परियोजना 340 करोड़ रुपये हैं जिसमें से 300 करोड़ रुपये ग्राहकों और व्यापारियों पर खर्च किए जाएंगे जबकि शेष 40 करोड़ रुपये जागरूकता और प्रचार अभियान पर खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल विजेताओं की संख्या 18.75 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

\*\*\*

AKT/NT/SKC

(Release ID: 1482430) Visitor Counter : 5

